भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान हैं। भारत के डेयरी सेक्टर की पहचान मास प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन बाय मास की है। भारत में डेयरी सेक्टर से जुड़े अधिकांश किसानों के पास या तो एक पशु है, दो पशु हैं या तीन पशु हैं। इन्हीं छोटे किसानों के परिश्रम और उनके पशुधन की वजह से आज भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। आज भारत के 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों को यह सेक्टर रोजगार मुहैया कराता है। भारत के डेयरी सेक्टर की यह बात शायद ही कहीं देखने को मिले। विश्व के अनेक गरीब किसानों के लिए यह एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल बन सकता है। - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

नई डेयरी नीति से बढ़ेगा निवेश युवाओं को मिलेगा रोजगार

5,000 करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य

1 लाख लोगों को हर साल मिलेगा रोजगार

योगी आदित्यनाथ सरकार की नई दुग्ध नीति 2022 सूबे को दस खरब डॉलर (वन ट्रिलियन डॉलर) की अर्थव्यवस्था को हासिल करने में ग्राम स्तर से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह नीति ग्रामीण परिवेश के लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ पोषण सुरक्षा में भी अपना योगदान देगी। यह नीति फरवरी में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करेगी, जिससे 5000 करोड़ रुपये का निवेश की उम्मीद है। इसके तहत ग्रीन फील्ड डेयरी की स्थापना व क्षमता विकास एवं प्रौद्योगिकी उच्चीकरण के लिए भी निवेश आकर्षित किया जाएगा। कैटल फील्ड प्लांट की स्थापना, रेफ्रिजरेटेड वैन, इंसुलेटेड मिल्क टैंक व अन्य कोल्ड चेन इंवेस्टमेंट्स और लघु उद्यम आधारित दुग्ध प्रसंस्करण के लिए निवेश पाने का लक्ष्य तय किया गया है।

- यूपी में बड़े डेयरी प्लांट लगाने के लिए 15 करोड़ रुपये अनुदान
- पशु आहार का प्लांट लगाने के लिए 7.50 करोड़ रुपये तक अनुदान
- अन्य कोल्ड चेन बनाने के लिए एक करोड़ रुपये तक मिलेगा अनुदान
- निजी निवेशकों को स्टांप व बिजली शुल्क में भी मिलेगी छूट
- पशुधन विभाग आवेदन के लिए तीन माह में विकसित करेगा अपना पोर्टल
- बिक्री के लिए 10 से 25 फीसदी उत्पादन बढ़ाने का रखा गया है लक्ष्य
- उन्नत किस्म के 10 हजार टन पशु आहार उत्पादन प्लांट लगाने का लक्ष्य
- चीज व आइस्क्रीम जैसे उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जाएगा

प्रदेश में नई दुग्ध नीति लागू की गई है। इसके तहत दुग्ध उद्योग सेक्टर को रियायत दी जा रही है।

अगले पांच वर्षों में पांच हजार करोड़ के पूंजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है।

नई नीति से प्रदेश में दुग्ध आधारित प्रसंस्करण के स्तर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाएगा।

बाजार के लिये उपलब्ध दूध को 44 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया जाएगा।

नई नीति के जरिए योगी सरकार पूंजीगत निवेश अनुदान के तहत सभी जिलों में दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाइयों की स्थापना अथवा विस्तारीकरण के लिये प्लान्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य एवं स्पेयर पार्ट्स की लागत का 10 प्रतिशत, अधिकतम 5 करोड़ की सीमा तक की सब्सिडी और पांच वर्षों के लिए 10 करोड़ रुपये ब्याज पर अनुदान देगी।

पशुपालन में लगे ज्यादातर लोग इसे पारंपरिक व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं। इस व्यवसाय को प्रौद्योगिकी और आधुनिक दृष्टिकोण से जोड़कर पशुपालकों की आय को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। पशुपालकों और किसानों के कारण उत्तर प्रदेश और भारत शीर्ष दुग्ध उत्पादक बन गए हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में नए ग्रीनफील्ड डेयरी संयंत्र शुरू करने के लिए काम तेजी से चल रहा है। ये संयंत्र अगले एक से दो साल में चालू हो जाएंगे। बाल्मिनी दुग्ध उत्पादक, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए एक अनुकरणीय मॉडल है।

- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री

कैटल फील्ड प्लांट की स्थापना, रेफ्रिजरेटेड वैन, इंसुलेटेड मिल्क टैंक और अन्य कोल्ड चेन इन्वेस्टमेंट, लघु उद्यम आधारित दुग्ध प्रोसेसिंग के लिए निवेश पाने का लक्ष्य तय किया गया है।

नई नीति से पशु पालकों को दूध के वाजिब दाम मिलने पर लोग बेहतर प्रजाति के गोवंश रखेंगे। ये लंबे समय तक पूरी क्षमता से दूध दें, इसके लिए संतुलित एवं पोषक पशु आहार देंगे।

इस तरह पशु आहार में प्रयुक्त चोकर, चुन्नी, खंडा, खली की भी मांग बढ़ेगी। संतुलित और पोषक आहार की मांग बढ़ने से इस तरह की इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इनको बनाने के लिए कृषि उत्पादों की मांग का लाभ किसानों को मिलेगा।

इंडस्ट्री लगने से इसका सीधा फायदा रोजगार के रूप में होगा।

इस नई नीति से हर साल करीब 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार मिलेगा।

योगी सरकार ने डेयरी क्षेत्र की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और नया आयाम देने में दुग्ध उत्पादन का अहम योगदान है। इसके साथ ही महिलाएं इससे जुड़कर आत्मनिर्भर और स्वयंसेवी बन रही हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए संकल्प लिया है।

प्रदेश में दूध उत्पादन की बढ़ोतरी में स्वयं सहायता समूह की भूमिका अहम है।

प्रदेश में जहां वर्ष 2016-17 में दूध का उत्पादन 264 लाख मीट्रिक टन होता था वही वर्तमान में 319 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा उत्पादन हो रहा है।

उत्तर प्रदेश की मेजबानी में सकुशल आयोजित हुआ वर्ल्ड डेयरी समिट

48 वर्ष के अंतराल के बाद भारत में आयोजित आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सकुशल संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का शुभारंभ करते हुए वैश्विक स्तर पर डेयरी उद्योग की अग्रणी हस्तियों को भारत में डेयरी क्षेत्र को सशक्त बनाने के अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए सराहना भी की। अंतरराष्ट्रीय मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों एवं पशुपालकों की आमदनी को दोगुना करने से जुड़े इस अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश को चुनने के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश आबादी की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और दुग्ध उत्पादन में भी पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। अन्तर्राष्ट्रीय डेयरी समिट के माध्यम से प्रदेश के किसानों एवं पशुपालकों को लाभ मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। समिट के माध्यम से आधुनिक तकनीक को जोड़कर प्रदेश के किसान एवं पशुपालक खेती के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन में अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे। उन्होंने नेशनल डेयरी फेडरेशन से सहयोग की अपेक्षा करते हुये प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया। मालूम हो कि 12 से 15 सितंबर तक आयोजित यह चार-दिवसीय आईडीएफ डब्ल्यूडीएस 2022, 'डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड' के विषय पर केंद्रित था। जहां उद्योग जगत के दिग्गजों, विशेषज्ञों, किसानों और नीति योजनाकारों सहित वैश्विक व भारतीय डेयरी हितधारकों का एक समूह है। इस आयोजन में विभिन्न देशों के लगभग 1500 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। इस तरह का पिछला शिखर सम्मेलन भारत में लगभग आधी सदी पहले 1974 में आयोजित किया गया था।

दुग्ध उत्पादन में शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश

16% हिस्सेदारी प्रदेश की देश के कुल उत्पादन में

319 लाख टन दूध

हर साल उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश जो देश में सर्वाधिक है

110

डेयरी प्लांट हैं संगठित क्षेत्र में, जिसमें सहकारी क्षेत्र के तहत 13 डेयरी प्लांट आते हैं।

406

ग्राम प्रतिदिन पहुंच गई प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता।

पांच साल पहले यह 352 ग्राम प्रति दिन थी

20%

की बढ़ोतरी हुई दुग्ध उत्पादन में प्रदेश में पिछले पांच वर्षों में

इससे जहां किसानों, पशुपालकों की आय में वृद्धि हुई वहीं दुग्ध समितियों में स्वयं सहायता समूह के जुड़ने से महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं।